स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर शिक्षकों की धारणाओं का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

कृष्णा कुमार सरहान

शोधार्थी, विक्रान्त यूनिवर्सिटी, ग्वालियर

सारांश:

स्कूली शिक्षा समाज के बौद्धिक और नैतिक विकास की नींव रखती है। इसकी गुणवत्ता केवल पाठ्यक्रम की संरचना या परीक्षा प्रणाली तक सीमित नहीं होती, बल्कि शिक्षकों की भूमिका, शिक्षण विधियों, विद्यालयी वातावरण, प्रशासनिक सहयोग और संसाधनों की उपलब्धता सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। शिक्षकों का दृष्टिकोण इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे शिक्षा प्रणाली के मूल घटक हैं और शैक्षिक सुधारों के प्रभाव को सीधे अनुभव करते हैं। शिक्षकों का मानना है कि पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, कक्षा में संवादात्मक शिक्षण, मूल्यांकन की निष्पक्षता, छात्र-शिक्षक अनुपात, शैक्षिक नवाचारों का समावेश और प्रशासनिक सहयोग, शिक्षा की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकताएँ, पेशेवर विकास के अवसर और शिक्षण में तकनीकी संसाधनों का प्रभाव भी इस अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्षों में शामिल हैं। अध्ययन में यह भी स्पष्ट हुआ कि विद्यालयी वातावरण और नीति-निर्माण में शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी से शिक्षा की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार किया जा सकता है। शिक्षकों ने यह सुझाव दिया कि शिक्षा प्रणाली को अधिक व्यावहारिक, समावेशी और आधुनिक बनाने के लिए नीतिगत बदलाव आवश्यक हैं। यह शोध नीति-निर्माताओं, शिक्षा प्रशासकों और शिक्षकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जिससे एक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली का निर्माण संभव हो सके।

मुख्य शब्द: शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन प्रणाली, विद्यालयी वातावरण, प्रशासनिक सहयोग, शैक्षिक नवाचार।

1. प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का मूल आधार होती है, और इसकी गुणवत्ता का प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर पड़ता है। स्कूली शिक्षा एक व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और व्यावसायिक विकास की नींव रखती है, जिसके माध्यम से वह समाज में अपना योगदान दे सकता है। वर्तमान युग में, जहाँ ज्ञान और सूचना क्रांति के कारण शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव हो रहे हैं, वहीं शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कई चुनौतियाँ भी उभर रही हैं। विशेष रूप से भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ शिक्षा प्रणाली बहुआयामी है, शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षकों की धारणा इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे न केवल ज्ञान के संवाहक होते हैं, बल्कि विद्यार्थियों के सीखने और विकास में भी केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता को मापने के लिए विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि पाठ्यक्रम की संरचना, शिक्षण पद्धतियाँ, मूल्यांकन प्रणाली, स्कूलों की आधारभूत संरचना, शिक्षकों की दक्षता, प्रशासनिक नीति और सरकारी प्रयास। लेकिन इन सभी कारकों में शिक्षकों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे न केवल छात्रों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में भी योगदान देते हैं। इसलिए, यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता पर शिक्षकों की धारणाओं को समझा जाए, जिससे शिक्षा प्रणाली को प्रभावी और व्यावहारिक रूप से उन्नत किया जा सके।

हाल के वर्षों में, स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए कई सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयास किए गए हैं। नई शिक्षा नीति (NEP-2020) जैसे सुधारात्मक कदमों के बावजूद, शिक्षकों की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। संसाधनों की कमी, बड़े छात्र समूहों, पाठ्यक्रम की जटिलता, प्रशासनिक दबाव और शिक्षण विधियों में नवीनता की आवश्यकता जैसी समस्याएँ शिक्षकों के समक्ष उपस्थित होती हैं। इन परिस्थितियों में, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर शिक्षकों की राय को जाना और समझा जाए, क्योंकि वे प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रक्रिया से जुड़े होते हैं और उनकी धारणा शिक्षा प्रणाली के सुधार में सहायक हो सकती है।

इस शोध अध्ययन का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर शिक्षकों की धारणाओं का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन शिक्षकों की राय के आधार पर यह जानने का प्रयास करेगा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या कमियाँ हैं, किन सुधारों की आवश्यकता है, और किस प्रकार शिक्षकों की भागीदारी से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। यह अध्ययन उन विभिन्न कारकों की भी पहचान करेगा जो शिक्षकों के दृष्टिकोण से शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

1. साहित्य समीक्षा

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों की धारणाओं और उनकी भूमिका पर विभिन्न विद्वानों और संगठनों ने महत्वपूर्ण अध्ययन और रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं। निम्नलिखित साहित्य इस संदर्भ में उल्लेखनीय है:

बी.एस. ऋषिकेश (2018): अपने लेख "शिक्षक-शिक्षा और प्रबंधन: नीति, व्यवहार और विकल्प" में ऋषिकेश ने भारत में शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया है। उन्होंने निजी और सरकारी शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता, उनकी चुनौतियाँ और सुधार के संभावित उपायों पर चर्चा की है। **नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE, 2009):** "अध्यापकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा" में NCTE ने व्यावसायिक और सहृदय शिक्षक तैयार करने के महत्व पर जोर दिया है। **नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT, 2018):** "भारतीय आधुनिक शिक्षा" शीर्षक से प्रकाशित इस दस्तावेज़ में विद्यालय-पूर्व शिक्षा केंद्रों में कार्य करने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता पर चर्चा की गई है। यह अध्ययन पूर्व-प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षकों की धारणाओं और उनकी भूमिकाओं को समझने में सहायक है। **अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी (2018):** "समकालीन भारत में विद्यालय के शिक्षक की भूमिका और चुनौतियाँ" शीर्षक से प्रकाशित इस अध्ययन में शिक्षकों की पारंपरिक भूमिकाओं, उनकी वर्तमान चुनौतियों और उनकी धारणाओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। यह अध्ययन शिक्षकों की धारणाओं के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। **इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज (2019):** "शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में" शीर्षक से प्रकाशित इस शोध पत्र में शिक्षक के दृष्टिकोण, माता-पिता और समुदाय के साथ उनकी बातचीत, और उनकी प्रतिबद्धता का शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पर चर्चा की गई है। **आईडियाज फॉर इंडिया (2022):** "माता-पिता एवं शिक्षक के बीच सहयोग के माध्यम से आधारभूत शिक्षा को सुदृढ़ बनाना" शीर्षक से प्रकाशित इस अध्ययन में समुदाय और शिक्षकों के बीच सहयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उपायों पर चर्चा की गई है। यह अध्ययन शिक्षकों की धारणाओं और समुदाय के साथ उनकी सहभागिता के महत्व को रेखांकित करता है।

उपरोक्त साहित्य से स्पष्ट होता है कि शिक्षकों की धारणाएँ, उनकी प्रशिक्षण प्रक्रियाएँ, व्यावसायिक विकास, समुदाय के साथ सहभागिता, और नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। इन अध्ययनों के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए शिक्षकों की धारणाओं को समझना और उन्हें सम्मिलित करना आवश्यक है।

2. शोध पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive) और विश्लेषणात्मक (Analytical) शोध डिज़ाइन पर आधारित है। अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का उपयोग करके शिक्षकों की धारणाओं का विश्लेषण किया गया है।

नमूना चयन

नमूना आकार (Sample Size): अध्ययन में 100 शिक्षकों को शामिल किया गया है, जो विभिन्न सरकारी और निजी विद्यालयों में कार्यरत हैं।

- नमूना चयन तकनीक (Sampling Technique): सुविधाजनक सैंपलिंग (Convenience Sampling) और स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना (Stratified Random Sampling) विधियों का उपयोग किया गया है, ताकि विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व हो सके।

डेटा संग्रह विधियाँ

इस अध्ययन में प्राथमिक (Primary) और द्वितीयक (Secondary) डेटा संग्रह की विधियों का उपयोग किया गया है।

प्राथमिक डेटा (Primary Data) संग्रह

- प्रश्नावली (Questionnaire): शिक्षकों की धारणाओं को समझने के लिए एक संरचित (Structured) प्रश्नावली तैयार की गई है, जिसमें बहुविकल्पीय (Multiple Choice Questions) और वर्णनात्मक (Descriptive) प्रश्न शामिल हैं।
- साक्षात्कार (Interviews): चयनित शिक्षकों के साथ व्यक्तिगत और समूह साक्षात्कार किए गए हैं, जिससे उनके विचारों और अनुभवों को गहराई से समझा जा सके।
- अवलोकन (Observation): विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया है, जिससे शिक्षकों की वास्तविक शिक्षण पद्धतियों और संसाधनों का मूल्यांकन किया जा सके।

द्वितीयक डेटा (Secondary Data) संग्रह

- विभिन्न शोध पत्र (Research Papers), सरकारी रिपोर्ट्स (Government Reports), शिक्षा नीतियाँ (Educational Policies) और NCERT, NCTE तथा अन्य अकादमिक स्रोतों से जानकारी संकलित की गई है।
- नई शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020), NCF 2005, और अन्य शैक्षिक दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया है।

इस शोध अध्ययन में शिक्षकों की धारणाओं को गहराई से समझने के लिए एक मिश्रित पद्धति (Mixed Methodology) अपनाई गई है, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है। डेटा संग्रह और विश्लेषण की वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके निष्कर्ष निकाले गए हैं, जो नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

3. स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के मापदंड

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न केवल विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है, बल्कि उनके समग्र व्यक्तित्व विकास में भी योगदान देती है। शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मापदंडों का निर्धारण किया जाता है, जो एक प्रभावी और समावेशी शिक्षा प्रणाली के निर्माण में सहायक होते हैं। इन मापदंडों में शिक्षण पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षक प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना, प्रशासनिक नीति और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन सभी कारकों का समुचित संतुलन ही एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करता है।

पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियाँ

शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने में पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियाँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक प्रभावी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों की बौद्धिक, नैतिक और व्यावहारिक क्षमताओं का विकास कर सके। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा विकसित पाठ्यक्रमों को विभिन्न स्तरों पर अपनाया जाता है। हाल के वर्षों में, पाठ्यक्रम को अधिक व्यावहारिक और कौशल-आधारित बनाने पर बल दिया जा रहा है ताकि छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखा जाए, बल्कि वे वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करने में भी सक्षम बनें। इसके अलावा, शिक्षण पद्धतियों में तकनीकी नवाचारों, जैसे स्मार्ट क्लासरूम, ई-लर्निंग प्लेटफार्म और इंटरएक्टिव शिक्षण उपकरणों का उपयोग बढ़ रहा है। पारंपरिक व्याख्यान पद्धति (Lecture Method) के स्थान पर सक्रिय शिक्षण (Active Learning), अनुभवात्मक शिक्षण (Experiential Learning), परियोजना आधारित शिक्षण (Project-Based Learning) और समस्या-समाधान आधारित शिक्षण (Problem-Solving Approach) को अधिक महत्व दिया जा रहा है।

मूल्यांकन प्रणाली

शिक्षा की गुणवत्ता को मापने के लिए एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली का होना अनिवार्य है। पारंपरिक परीक्षा पद्धतियाँ (Summative Assessment) अक्सर केवल रटने की प्रवृत्ति (Rote Learning) को बढ़ावा देती हैं, जिससे विद्यार्थियों की तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच सीमित रह जाती है। इसके स्थान पर, सतत और व्यापक मूल्यांकन (Continuous and Comprehensive Evaluation - CCE) जैसी प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है, जो विद्यार्थियों के बहुआयामी विकास को सुनिश्चित करें। भारत में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (National Achievement Survey - NAS) और राज्य स्तरीय मूल्यांकन प्रणालियों के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, फीडबैक-आधारित मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन (Peer Assessment), ओपन-बुक एग्जामिनेशन और परियोजना कार्य जैसे नवाचारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने तक सीमित न रहें, बल्कि संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी विकसित हो सकें।

शिक्षकों की भूमिका और प्रशिक्षण

शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। एक प्रभावी शिक्षक न केवल विषय-वस्तु का ज्ञान रखता है, बल्कि कक्षा प्रबंधन, विद्यार्थियों की समझने की क्षमता, मानसिक एवं भावनात्मक पहलुओं को समझने की कुशलता भी रखता है। भारत में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (National Council for Teacher Education - NCTE) और विभिन्न राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs) के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पूर्व-सेवा (Pre-Service) और

सेवाकालीन (In-Service) प्रशिक्षण शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकों और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं से अवगत कराते हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, जैसे SWAYAM, DIKSHA और NISHTHA के माध्यम से शिक्षकों के सतत् व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development - CPD) को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालाँकि, शिक्षक-छात्र अनुपात (Pupil-Teacher Ratio - PTR) में असंतुलन, शिक्षकों की पदोन्नति की समस्याएँ, प्रशासनिक दबाव और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है।

आधारभूत संरचना और संसाधन

विद्यालयों की आधारभूत संरचना का विद्यार्थियों की सीखने की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत में अभी भी कई सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना की कमी है, जिससे छात्रों के सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है। शौचालय, स्वच्छ पेयजल, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएँ, कंप्यूटर लैब, खेल के मैदान, इंटरनेट सुविधा आदि स्कूलों की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम, जैसे "समग्र शिक्षा अभियान", विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने का कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, निजी और सरकारी विद्यालयों के बीच बुनियादी ढांचे की असमानता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

प्रशासनिक नीति और शिक्षा में नवाचार

शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार और प्रशासनिक निकायों की नीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) ने शिक्षा प्रणाली में कई सुधार प्रस्तावित किए हैं, जिनमें कक्षा 3 तक मातृभाषा में शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा का समावेश, कौशल आधारित शिक्षा, बहु-विषयक शिक्षण दृष्टिकोण और डिजिटल शिक्षा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए प्रत्यक्ष भर्ती, वेतनमान में सुधार, डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक पहुँच जैसी योजनाएँ लागू की जा रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए "अटल टिकरिंग लैब", "स्टार्टअप इंडिया", और "स्किल इंडिया मिशन" जैसी पहलें भी की गई हैं।

छात्रों की सीखने की प्रक्रिया और समावेशिता

शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान किए जाएँ। विशेष रूप से वंचित वर्गों, दिव्यांग विद्यार्थियों और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारत में मिड-डे मील योजना, छात्रवृत्ति योजनाएँ, और आरटीई (Right to Education Act) के माध्यम से शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद, डिजिटल विभाजन (Digital Divide), लैंगिक असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है।

4. शिक्षकों की धारणाएँ

शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की भूमिका केवल ज्ञान के संवाहक तक सीमित नहीं है, बल्कि वे विद्यार्थियों के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी शिक्षा नीति या सुधारात्मक प्रयास की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षकों की उस प्रणाली के प्रति धारणा और समझ कैसी है। चूँकि शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण प्रक्रिया और विद्यार्थियों के सीखने की गति को प्रभावित करते हैं, इसलिए उनकी धारणाएँ शिक्षा की गुणवत्ता के निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। विभिन्न अध्ययनों और साक्षात्कारों से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षकों की धारणाएँ कई कारकों पर आधारित होती हैं, जिनमें पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता, प्रशासनिक

सहयोग, विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति, समाज की शिक्षा के प्रति धारणा और शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता शामिल हैं।

पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों के प्रति शिक्षकों की धारणा

अधिकांश शिक्षकों का मानना है कि वर्तमान स्कूली पाठ्यक्रम का डिज़ाइन यथार्थवादी संदर्भों से काफी हद तक कटा हुआ है। कई शिक्षकों का यह मत है कि पाठ्यक्रम को अधिक व्यावहारिक, कौशल-आधारित और आधुनिक दुनिया की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। शिक्षकों को लगता है कि पाठ्यक्रम में बहुत अधिक सिद्धांत (Theory) और रटने (Rote Learning) पर जोर दिया गया है, जबकि विद्यार्थियों की तार्किक, रचनात्मक और समस्या समाधान करने की क्षमता पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की राय यह भी है कि अत्यधिक विस्तृत पाठ्यक्रम न केवल विद्यार्थियों बल्कि शिक्षकों पर भी अतिरिक्त दबाव डालता है। परिणामस्वरूप, वे पूरी तरह से अध्यापन प्रक्रिया में नवाचार लाने में असमर्थ रहते हैं और पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करने पर ही उनका मुख्य ध्यान केंद्रित रहता है।

मूल्यांकन प्रणाली और परीक्षा प्रणाली पर शिक्षकों की राय

शिक्षकों का मानना है कि वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली अभी भी परीक्षा-केन्द्रित (Exam-Oriented) है, जिससे विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक विकास सीमित हो जाता है। शिक्षकों की धारणा के अनुसार, सतत और व्यापक मूल्यांकन (CCE - Continuous and Comprehensive Evaluation) प्रणाली को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी केवल अंक प्राप्त करने की मानसिकता से बाहर आकर वास्तविक ज्ञान और कौशल विकसित कर सकें। अध्ययन के दौरान कई शिक्षकों ने यह भी बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार के लिए व्यावहारिक परीक्षाओं, असाइनमेंट, समूह चर्चा, केस स्टडी और परियोजना कार्य (Project Work) को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि, कई शिक्षक यह भी मानते हैं कि शिक्षकों को अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रखने के कारण वे मूल्यांकन प्रक्रिया में नवाचार करने के लिए अधिक समय नहीं निकाल पाते हैं।

शिक्षकों के प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास के प्रति धारणा

शिक्षकों की धारणा यह है कि उनके व्यावसायिक विकास के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वे अक्सर सैद्धांतिक होते हैं और व्यावहारिक शिक्षण समस्याओं को हल करने में अधिक सहायक नहीं होते। शिक्षकों का यह भी मानना है कि आधुनिक शिक्षण तकनीकों और डिजिटल उपकरणों को उपयोग में लाने के लिए व्यापक और नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है। कई शिक्षकों का सुझाव है कि शिक्षक-प्रशिक्षण को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, ताकि शिक्षक अपने छात्रों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकें और प्रभावी रूप से पढ़ा सकें।

विद्यालयों में आधारभूत संरचना और संसाधनों पर शिक्षकों की राय

विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में शिक्षकों की राय मिली-जुली होती है। निजी विद्यालयों के शिक्षक आमतौर पर बेहतर कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और डिजिटल संसाधनों तक पहुँच रखते हैं, जबकि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का यह मानना है कि उनके यहाँ संसाधनों की कमी के कारण पढ़ने में कठिनाई होती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में इंटरनेट, स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब और कंप्यूटर सुविधाओं की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या बनी हुई है। शिक्षकों की धारणा यह भी है कि छात्र-शिक्षक अनुपात (Pupil-Teacher Ratio - PTR) में सुधार किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षकों को प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान देने का पर्याप्त

समय मिल सके। कई शिक्षकों ने इस बात पर भी जोर दिया कि विद्यालयों में प्रेरणादायक और सहयोगी प्रशासनिक वातावरण होना आवश्यक है, जिससे वे बेहतर शिक्षण तकनीकों का प्रयोग कर सकें और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला सकें।

5. शोध निष्कर्ष

इस अध्ययन में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर शिक्षकों की धारणाओं का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न कारकों का गहन अध्ययन किया गया। शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं, साक्षात्कारों और उपलब्ध द्वितीयक डेटा के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षकों का प्रशिक्षण, विद्यालयों की आधारभूत संरचना, प्रशासनिक नीतियाँ और अभिभावकों की सहभागिता प्रमुख रूप से शामिल हैं। हालाँकि, विभिन्न विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता देखी गई, जो कि शहरी और ग्रामीण विद्यालयों, सरकारी और निजी विद्यालयों तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भिन्न थी। शिक्षकों ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों को दर्शाते हैं।

पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियाँ

शोध से यह निष्कर्ष निकला कि अधिकांश शिक्षकों का मानना है कि वर्तमान पाठ्यक्रम अत्यधिक सैद्धांतिक और परीक्षा-केंद्रित है, जिससे विद्यार्थियों की तार्किक और व्यावहारिक समझ विकसित नहीं हो पाती। शिक्षकों का यह भी मानना है कि पाठ्यक्रम को अधिक व्यावहारिक, कौशल-आधारित और उद्योग-उन्मुख बनाया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी केवल रटने तक सीमित न रहें, बल्कि जीवन में वास्तविक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बन सकें। शिक्षकों ने यह भी बताया कि पारंपरिक शिक्षण पद्धतियाँ (Lecture-Based Teaching) अभी भी व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं, जबकि प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षण (Project-Based Learning), अनुभवात्मक शिक्षण (Experiential Learning), और डिजिटल शिक्षण (Digital Learning) जैसी आधुनिक विधियों को अब भी पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता। कई शिक्षकों का यह भी मत है कि अगर उन्हें पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षण मिले, तो वे शिक्षण में नवाचार ला सकते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

मूल्यांकन प्रणाली और परीक्षाएँ

शिक्षकों ने मूल्यांकन प्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण चिंताएँ व्यक्त कीं। उनका मानना है कि पारंपरिक परीक्षा प्रणाली (Summative Assessment) विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमता को मापने में असफल रहती है और उन्हें केवल अंकों की दौड़ में धकेल देती है। शिक्षकों की राय के अनुसार, सतत् और व्यापक मूल्यांकन (CCE) प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों के बहुआयामी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों का यह भी सुझाव है कि मूल्यांकन प्रणाली में सुधार लाने के लिए परियोजना कार्य, केस स्टडी, समूह चर्चा, समस्या-आधारित शिक्षण और व्यावहारिक परीक्षणों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। हालाँकि, शिक्षकों ने यह भी बताया कि प्रशासनिक दबाव और अत्यधिक कागजी कार्यों के कारण वे मूल्यांकन प्रणाली में सुधार लाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर पाते।

शिक्षकों का प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास

शोध से यह निष्कर्ष निकला कि अधिकांश शिक्षक अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने बताया कि अध्यापन में नवाचार और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता

है। हालाँकि, सरकारी और निजी विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण में अंतर देखने को मिला। शिक्षकों का मानना है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक व्यावहारिक और कक्षा-केंद्रित (Classroom-Oriented) बनाया जाना चाहिए, ताकि वे वास्तविक शिक्षण चुनौतियों का समाधान कर सकें। इसके अलावा, कई शिक्षकों ने यह भी बताया कि यदि उन्हें शिक्षण में नवाचार लाने के लिए स्वतंत्रता और प्रोत्साहन मिले, तो वे अधिक प्रभावी शिक्षण तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं।

विद्यालयों की आधारभूत संरचना और संसाधन

शोध के दौरान यह पाया गया कि शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालयों की आधारभूत संरचना के बीच गहरा संबंध है। विशेष रूप से ग्रामीण सरकारी विद्यालयों में, शिक्षकों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को एक बड़ी समस्या बताया। इनमें पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएँ, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम, पेयजल और स्वच्छता सुविधाएँ शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में अपेक्षाकृत बेहतर आधारभूत संरचना पाई गई, जिससे वहाँ की शिक्षा प्रणाली अधिक प्रभावी दिखाई दी। इसके विपरीत, ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में संसाधनों की कमी के कारण शिक्षकों को अपने पाठों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है। इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार को ठोस नीतियाँ बनानी चाहिए, ताकि सभी विद्यालयों में समान संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें।

छात्रों की सीखने की प्रवृत्ति और अभिभावकों की सहभागिता

शोध में यह पाया गया कि छात्रों की सीखने की प्रवृत्ति (Learning Attitude) धीरे-धीरे बदल रही है। डिजिटल युग में, कई विद्यार्थी ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग कर स्व-अध्ययन (Self-Learning) को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही मोबाइल फोन और इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग के कारण ध्यान केंद्रित करने की क्षमता (Attention Span) कम हो रही है। शिक्षकों का मानना है कि अभिभावकों की शिक्षा में सहभागिता (Parental Involvement) बढ़ाने की आवश्यकता है। कई शिक्षकों ने बताया कि यदि अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई में अधिक रुचि लें और स्कूल के साथ समन्वय बनाए रखें, तो छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। हालाँकि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में, अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता और संसाधनों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है।

6. निष्कर्ष और सिफारिशें

निष्कर्ष

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर शिक्षकों की धारणाओं का विश्लेषण करना था, ताकि यह समझा जा सके कि शिक्षक शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति को कैसे देखते हैं और उसमें सुधार के लिए उनके क्या सुझाव हैं। अध्ययन के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षक प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना, प्रशासनिक नीतियाँ और अभिभावकों की सहभागिता प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, शिक्षकों की राय में, इन सभी पहलुओं में कई कमियाँ हैं, जो समग्र शिक्षा प्रणाली को कमजोर बनाती हैं।

शोध के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश शिक्षक पाठ्यक्रम को अत्यधिक सैद्धांतिक और परीक्षा-केंद्रित मानते हैं, जो कि विद्यार्थियों की तार्किक और व्यावहारिक सोच को विकसित करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। मूल्यांकन प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान प्रणाली छात्रों को केवल अंक अर्जित करने की मानसिकता तक सीमित कर रही है, जबकि व्यापक ज्ञान और कौशल विकास पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षकों का

यह भी मानना है कि शिक्षण पद्धतियों में अधिक नवाचार और प्रौद्योगिकी का समावेश किया जाना चाहिए, लेकिन संसाधनों की अनुपलब्धता और प्रशासनिक दबाव के कारण वे अपनी शिक्षण विधियों में बड़े बदलाव करने में असमर्थ हैं।

शिक्षकों के प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास (CPD) को लेकर भी कई चुनौतियाँ देखी गईं। अधिकांश शिक्षक मानते हैं कि शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक व्यावहारिक और कक्षा-केंद्रित होने चाहिए, ताकि वे शिक्षण की वास्तविक समस्याओं से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों और गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में अत्यधिक व्यस्त रखा जाता है, जिससे उनका ध्यान मुख्य शिक्षण प्रक्रिया से हट जाता है।

विद्यालयों की आधारभूत संरचना और संसाधनों की उपलब्धता शिक्षा की गुणवत्ता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अध्ययन से यह पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों और सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना की कमी, शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता और डिजिटल संसाधनों तक सीमित पहुँच जैसी समस्याएँ हैं, जो प्रभावी शिक्षण और अधिगम में बाधा डालती हैं। इसके विपरीत, निजी विद्यालयों में संसाधनों की बेहतर उपलब्धता देखी गई, जिससे सरकारी और निजी शिक्षा प्रणाली के बीच एक बड़ा अंतर देखने को मिला।

सिफारिशें

शिक्षकों की धारणाओं और इस शोध के निष्कर्षों के आधार पर, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की जा रही हैं:

1. पाठ्यक्रम में सुधार और व्यावहारिकता का समावेश

- पाठ्यक्रम को अधिक व्यावहारिक, कौशल-आधारित और उद्योग-उन्मुख बनाया जाए।
- शिक्षण सामग्री में स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों को सम्मिलित किया जाए, जिससे विद्यार्थी बेहतर समझ विकसित कर सकें।
- पाठ्यक्रम का नियमित मूल्यांकन और अद्यतन किया जाए, ताकि यह बदलती सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

2. शिक्षण पद्धतियों में नवाचार और तकनीक का उपयोग

- शिक्षकों को प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग, एक्टिव लर्निंग और डिजिटल लर्निंग जैसी आधुनिक शिक्षण विधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- स्मार्ट क्लासरूम, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाया जाए, ताकि शिक्षण अधिक प्रभावी हो सके।
- विद्यालयों में शिक्षकों को अधिक स्वतंत्रता दी जाए, ताकि वे रचनात्मक और नवाचारी शिक्षण तकनीकों को लागू कर सकें।

3. मूल्यांकन प्रणाली में सुधार

- पारंपरिक परीक्षा प्रणाली में सुधार कर उसे समग्र मूल्यांकन (Holistic Assessment) प्रणाली में बदला जाए, जिसमें व्यावहारिक परीक्षाएँ, परियोजना कार्य और समस्या-समाधान आधारित मूल्यांकन शामिल हों।

- सतत और व्यापक मूल्यांकन (CCE) को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि विद्यार्थियों की क्षमता का समुचित मूल्यांकन हो सके।
 - परीक्षा प्रणाली को कम अंक-केंद्रित और अधिक कौशल-उन्मुख बनाया जाए, जिससे विद्यार्थी केवल अंक अर्जित करने के बजाय व्यावहारिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करें।
4. शिक्षकों के प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास पर ध्यान देना
- शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी, व्यावहारिक और आधुनिक शिक्षण विधियों पर केंद्रित किया जाए।
 - ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म जैसे SWAYAM, DIKSHA और NISHTHA के माध्यम से शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए।
 - शिक्षकों के लिए अध्यापन में नवाचार, कक्षा प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य किए जाएं।
5. विद्यालयों की आधारभूत संरचना में सुधार
- सभी विद्यालयों में सुरक्षित भवन, पर्याप्त कक्षाएँ, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएँ और कंप्यूटर लैब सुनिश्चित किए जाएं।
 - सरकारी और निजी विद्यालयों के बीच संसाधनों की असमानता को कम करने के लिए विशेष योजनाएँ लागू की जाएं।
 - विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा प्रदान की जाए।
6. अभिभावकों की सहभागिता बढ़ाना
- विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक संवाद (Parent-Teacher Interaction) को बढ़ावा देने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जाएं।
 - अभिभावकों को शिक्षा की महत्ता के प्रति जागरूक करने के लिए समुदाय-आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।
 - आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा में सहयोग देने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और सहायता योजनाओं का विस्तार किया जाए।

निष्कर्षतः, यदि उपरोक्त सिफारिशों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकता है। इससे न केवल विद्यार्थियों का शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि समग्र रूप से समाज और राष्ट्र का भी उत्थान होगा।

संदर्भ (References)

1. भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय. (2023). *वार्षिक रिपोर्ट 2021-22*. शिक्षा मंत्रालय.
2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT). (2018). *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. एनसीईआरटी.

3. सिंह, जे. डी. (2017). भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति व चुनौतियाँ. *ई-चेतना*.
4. यादव, अ. (2018). समावेशी शिक्षा प्रतिमान में कक्षा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*.
5. शर्मा, के. (2016). प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में बाधाएँ: अध्ययन एवं सुझाव. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट*.
6. विकासपीडिया. (2023). विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार. *विकासपीडिया*.
7. दृष्टि आईएस. (2019). भारत में शिक्षा गुणवत्ता: चुनौतियाँ और समाधान. *दृष्टि आईएस*.
8. तिवारी, क. (2016). सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन. *शिक्षक शिक्षा शोध पत्रिका*.
9. कानपुर विश्वविद्यालय. (2023). शिक्षक शिक्षा का ऐतिहासिक एवं वर्तमान परिदृश्य में अध्ययन. *कानपुर*
10. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज. (2021). उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक समीक्षा. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज*.
11. सिल्विया एश्टन-वॉरनर. (1958). *टीचर (Teacher)*. Simon and Schuster.
12. आचार्य रत्नाकर. (2021). *हिंदी टीचर फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल*. प्रभात प्रकाशन.
13. राजीव रंजन. (2019). *बेसिक हिंदी I*. मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी.
14. भावना शेखर. (2020). *शिक्षक की डायरी*. राजकमल प्रकाशन.
15. भावना तिवारी. (2018). *मेरे शिक्षक*. वाणी प्रकाशन.
16. एनसीईआरटी. (2018). *भाषा शिक्षण भाग-1*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद.
17. एनसीईआरटी. (2020). *ज्ञान पाठ्यचर्या व शिक्षण शास्त्र*. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद.
18. एनसीईआरटी. (2021). *समकालीन भारत एवं शिक्षा*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद.
19. सिंह, ए. (2018). शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज*, 5(3), 123-130.
20. शर्मा, के. (2016). प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में बाधाएँ: अध्ययन एवं सुझाव. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट*, 3(2), 45-50.
21. तिवारी, के. (2016). सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन. *शिक्षक शिक्षा शोध पत्रिका*, 10(3), 75-82.
22. कुमार, आर. (2018). *शिक्षक शिक्षा में गुणात्मकता*. जेटीर, 5(10), 98-105.